

## श्री दिनेश चंद्रा, सदस्य, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा) का जीवनवृत्त

- श्री दिनेश चन्द्रा 25 मार्च, 2019 से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (जल विद्युत) का पद संभाल रहे हैं। वे सदस्य (ग्रिड संचालन और वितरण) के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।
- उन्होंने आईआईटी, रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक किया और उसके बाद आईआईटी, रुड़की से ही कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1986 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) में कार्य किया।
- श्री दिनेश चन्द्रा ने अपने करियर की शुरुआत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी, जिसे पहले एनआरईबी के नाम से जाना जाता था) में अपनी तैनाती के साथ की और वर्ष 2007 तक उस कार्यालय में अपनी सेवाएँ दीं। जनवरी, 2008 से, वह केविप्रा मुख्यालय में कार्य कर रहे हैं। केविप्रा/एनआरपीसी में अपनी 34 वर्षों की सेवा के दौरान, उन्होंने विद्युत क्षेत्र में विविध विषयों पर कार्य किया है, जैसे रियल टाइम सिस्टम ऑपरेशन, ग्रिड संचालन का ऑफ-लाइन विश्लेषण, वाणिज्यिक पहलू, प्रणाली सुरक्षा, ऊर्जा लेखांकन, सीईआरसी/एसईआरसी संबंधित मामले, आईटी आधारित प्रणाली की अधिप्राप्ति तथा संचालन और अनुरक्षण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्रिड की गड़बड़ी का विश्लेषण और ग्रिड गड़बड़ी की रिपोर्ट तैयार करना आदि। उन्होंने कई विकसित देशों में विद्युत क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।
- श्री दिनेश चंद्रा ने 1980 दशक के उत्तरार्ध में राउंड द क्लॉक शिफ्ट में वास्तविक समय प्रणाली के संचालन को संभालते हुए, नियंत्रण कक्ष में उपयोग की जा रही विभिन्न आवधिक रिपोर्टों के कम्प्यूटरीकरण की स्वयं पहल की और बाद में लगभग सभी रिपोर्टों का कम्प्यूटरीकरण किया, जो एनआरईबी में मैनुअली तैयार की जा रही थी। उन्होंने साप्ताहिक और मासिक ऊर्जा खाते तैयार करने और जारी करने के लिए आरपीसी द्वारा

उपयोग के लिए एबीटी आधारित ऊर्जा लेखांकन सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के द्वारा उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) को व्यावहारिक रूप देने में प्रमुख भूमिका निभाई।

- वर्ष 2010-11 में निदेशक (आईटी) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान केविप्रा में उन्होंने सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस प्रणाली ने केविप्रा के विभिन्न प्रभागों द्वारा काफी मात्रा में आवधिक रिपोर्ट तैयार करने और जारी करने हेतु इसकी दक्षता में सुधार किया। वे जुलाई 2012 की ग्रिड गड़बड़ी पर जांच समिति के साथ भी जुड़े थे और उन्होंने न केवल गड़बड़ियों / सिफारिशों की तैयारी और रिपोर्ट के विश्लेषण में योगदान दिया, बल्कि राष्ट्रीय विद्युत समिति (एनपीसी) के सदस्य-सचिव के रूप में उन सिफारिशों के कार्यान्वयन में भी योगदान दिया। इन्होंने विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के प्रचालनीकरण की प्रक्रिया में भी काफी योगदान किया।